हिन्दी प्रादेशिक समाचार

आकाशवाणी चंडीगढ़

(तिथि 21 अप्रैल 2026, समय 13:05 (5 मिनट)

केंद्र सरकार ने किसानों के लाभ और घरेलू बाजारों की स्थिरता के लिए अतिरिक्त 25 लाख मीट्रिक टन गेहूं के निर्यात को अपनी मंजूरी दे दी है। यह निर्णय उत्पादन अनुमानों, स्टॉक की उपलब्धता और मूल्य रुझानों की समीक्षा के बाद लिया गया है। केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बताया कि इस साल रबी फसल में गेहूं की बुवाई बढ़कर 334 लाख हेक्टेयर से ज्यादा हो गई है।

**********

**********

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण-एफएसएसएआई ने खाद्य पदार्थों में अश्वगंधा की पत्तियों के प्रयोग पर अब प्रतिबंध लगा दिया है। प्राधिकरण ने खाद्य कारोबार संचालकों को निर्देश दिया है कि वे निर्धारित मानकों के अनुरूप अपने उत्पादों में केवल अश्वगंधा की जड़ और उसके अर्क का ही इस्तेमाल करें। प्राधिकरण ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य और सुरक्षा आयुक्तों को कड़ी निगरानी रखने और नियमों का पालन न करने की स्थिति में उचित कार्रवाई के निर्देश भी दिये हैं।

**********

**********

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी-एनटीए ने जेईई मेन सत्र 2 के परिणाम जारी कर दिए हैं। इस परीक्षा में कुल 2 लाख 50 हजार 182 अभ्यर्थी जेईई एडवांस्ड के लिए योग्य घोषित हुए हैं।

**********

**********

हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि भूमि वसूली अधिनियम के तहत स्थायी रूप से काटे गए बिजली कनेक्शनों वाले उपभोक्ताओं से बकाया राशि की वसूली हेतु 15 दिनों के भीतर नोटिस जारी किए जाएंगे।

श्री विज ने बताया कि राज्य में कुल 8,200 करोड़ रुपये की बकाया राशि की वसूली की जानी है। उन्होंने कहा की संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय-सीमा में वसूली प्रक्रिया पूर्ण करने और किसी प्रकार की ढिलाई न बरतने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि जिन उपभोक्ताओं के यहां बिजली चोरी के मामले सामने आए हैं, उन्हें एक बार पुनः भूमि वसूली अधिनियम के तहत नोटिस जारी कर बकाया राशि जमा करने का अवसर दिया जाएगा।

बिजली आपूर्ति को लेकर उन्होंने कहा कि राज्य की बिजली कंपनियां उपभोक्ताओं को निर्बाध एवं गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बिजली आपूर्ति से संबंधित शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। शहरी क्षेत्रों में खराब ट्रांसफार्मरों को 2 घंटे तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 4 घंटे के भीतर बदलना अनिवार्य किया गया है।

**********

**********

जनगणना 2027 में डिजिटल भागीदारी को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पंजाब के राज्यपाल एवं संघ शासित प्रदेश, चंडीगढ़

के प्रशासक  गुलाब चंद कटारिया ने कल ऑनलाइन जनगणना पोर्टल के माध्यम से अपनी स्व-गणना पूर्ण की। स्व-गणना की इस प्रक्रिया में जनगणना संचालन निदेशक डॉ. नवजोत खोसा और सह-प्रधान जनगणना अधिकारी एवं चंडीगढ़ के उपायुक्त  निशांत कुमार यादव ने उनका सहयोग किया।

स्व-गणना करके राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक ने सभी नागरिकों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए उन्हें इस सुविधाजनक एवं सुरक्षित डिजिटल प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि स्व-गणना के माध्यम से नागरिक अपनी सुविधानुसार ऑनलाइन जनगणना विवरण भर सकते हैं, जिससे सटीकता सुनिश्चित होती है और समय की भी बचत होती है।

इस दौरान  राज्यपाल ने प्रभावी योजना निर्माण एवं नीति निर्धारण के लिए सटीक आंकड़ों के महत्व पर बल दिया। उन्होंने सभी नागरिकों से भी स्व गणना में सहयोग का आह्वान किया।

**********

**********

हरियाणा के लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा ने अधिकारियों को हिसार खानक रोड की विशेष मरम्मत करवाए जाने के निर्देश दिए हैं। यह सड़क मार्ग अधिक जलभराव के कारण से हिसार की सीमा में कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त हो गया था।

एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि सडक़ की विशेष मरम्मत के लिए एक करोड़ 15 लाख 22 हजार रुपये की राशि का प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिसे जल्द ही सरकार से अनुमति मिल जाएगी। इसके उपरांत मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया जाएगा।

इसी प्रकार से मंत्री द्वारा पातन से मुकलान-रावलवास सडक़ मार्ग की विशेष मरम्मत के निर्देश भी दिए गए हैं। जिसके लिए 69 लाख 87 हजार रुपये का प्रस्ताव तैयार किया गया है और सरकार की स्वीकृति हेतु भेज दिया गया है। यह सडक़ मार्ग भी अत्यधिक जलभराव के कारण कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त हो गया था।

**********

**********

हरियाणा के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और राज्य की चिरायु योजना की प्रगति के आकलन को लेकर  कल एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।

डॉ. सुमिता मिश्रा ने कहा कि योजना के कामकाज में थर्ड-पार्टी ऑडिट अनिवार्य किया जाएगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आयुष्मान भारत प्रक्रिया में कोई धोखाधड़ी न हो। उन्होंने निर्देश दिया कि आयुष्मान भारत के तहत सरकारी कॉलेजों और मेडिकल संस्थानों से क्लेम को कैसे बढ़ाया जा सकता है, इसकी जांच के लिए रणनीति बनाई जाए।